University of Groningen

Unruly urbanisation on Delhi's fringe

Bentinck, J.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2000

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bentinck, J. (2000). *Unruly urbanisation on Delhi's fringe: Changing patterns of land use and livelihood*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-07-2024

SUMMARIES IN HINDI AND DUTCH

हिन्दी संक्षेप

बेतरतीब बदलाव: दिल्ली की सीमा पर बसे गांवों का शहरीकरण
भूमि प्रयोग, पारिवारिक आय और पर्यावरणीय परिस्थितियों में आते परिवर्तन

योहन बैंटिंक
भूगोल विभाग
ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय
नीदरलैंड

इस शोध निबंध का प्रमुख बिंदु दिल्ली की शहर-गांव सीमा पर बसे गांवों में शहरीकरण के प्रभावों का जायज़ा लेना है। इन प्रभावों के चार पहलू हैं: पहला, जमीन के इस्तेमाल का तरीका या पैटर्न; दूसरा, "पात्र" जो जमीन के इस्तेमाल और स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक भूमिका निभाते हैं; तीसरा, ग्रामीण आबादी में पेशे और आय के लिहाज से आये बदलाव; और चौथा, पर्यावरणीय हालात।

महानगर दिल्ली की आबादी 1.3 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और अभी भी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि (जिसमें से आधी से ज्यादा विस्थापन के कारण है), आर्थिक गतिविधियों में इजाफ़े और गांवों के शहर में समाहित होते जाने के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्र के फ़ैलाव के कारण हर दशक के साथ लगभग 40 नये गांव शहर की परिधि के भीतर पहुंच जाते हैं। जो गांव अभी भी देहाती पट्टी के भीतर ही स्थित है उनमें भी जबर्दस्त बदलाव देखे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष आर्थिक वातावरण ('स्थान') और पहुंच ('परिस्थिति') में बदलावों से पेशेगत बदलाव आ रहे हैं जो या तो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक आवाजाही के रूप में दिखायी देते हैं या गैर कृषि गतिविधियों के हावी होते जाने के रूप में। वैसे तो पेशागत बदलावों के इलाकावार पैटर्न को जनगणना संबंधी आंकड़ों के ब्यौरों से भी कुछ हद तक समझा जा सकता है लेकिन हमारा मकसद इस पूरे घटनाक्रम के महीने ब्यौरे और तौर तरीकों की गहन पड़ताल करना था।

शोध के अनुभवजन्य भाग के लिये एक भिन्न तरीका चुना गया था। हमारे शोध का क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के अलीपुर ब्लॉक के आठ गांव थे। आजीविका संबंधी मुद्दों को समझने की दिशा में घरेलू सर्वे और विस्तृत साक्षात्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण रहे। भूमि प्रयोग का आंकलन करने के लिये सैटेलाईट चित्रों का प्रयोग किया गया और नीतिगत मुद्दों के बारे में पड़ताल के लिये मीडिया (समाचार पत्रों) का सहारा लिया गया।

अध्ययन का पहला भाग भूमि प्रयोग के बारे में है। जमीन के प्रयोग के विषय में निरंतर परिवर्तनशीलता और असमानता दिल्ली जैसे तेजी से फ़ैलते महानगरों की सीमाओं पर स्थित आबादी की एक सामान्य विशेषता है। ज्यादातर जमीन सामान्य कृषि के दायरे से निकलकर शहरी कामों में जा रही है, जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और बेतहाशा व बार-बार की खरीद बिक्री से जमीन का मालिकाना ढांचा

बदलता रहता है। निम्नलिखित विशिष्ट प्रकार के भूमि प्रयोग बताते हैं कि समय और स्थान दोनों के लिहाज से जमीन का ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में रूपांतरण जारी है:

1. सामान्य फसलें (शहरीकरण के कारण घटती जा रही हैं)
2. फूलों की खेती (शहरी बाजार के आकर्षण के चलते धीरे-धीरे बढ़ रही है)
3. जंगल / पंचायती जमीन / बाग (जनसंख्या दबाव और फैलती शहरी परिधि के कारण घट रहे हैं)
4. खाली जमीन (कुल मिलाकर स्थिर है, लेकिन असल में यह जमीन के ग्रामीण से शहरी रूपांतरण के बीच एक विशिष्ट बिंदु है और उसे इस अवस्था में मूलत: दामों में इजाफे की उम्मीद के साथ रखा गया है)
5. फार्महाऊस (बढ़ रहे हैं: ये ऐसे रईसों की ऐशगाहें हैं जिनके पास या तो बेहद मामूली खेती है या बिल्कुल खेती नहीं है)।
6. ईंट भट्ठे (फिलहाल हमारे शोध के क्षेत्र में व्यवहारत: प्रतिबंधित हैं लेकिन दूसरे ग्रामीण क्षेत्रें में दूर-दूर तक फैलते जा रहे हैं)
7. उत्खनन (खुदाई जो ज्यादातर ईंट भट्ठों के साथ जुड़ी है)
8. आधारभूत ढांचा (बढ़ रहा है)
9. निर्माण (तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर (गैर कानूनी) कॉलोनियों, उद्योग और गोदामों के रूप में)

सैटेलाईट छवियों का प्रयोग करते हुए रिमोट सेंसिंग (आर एस) तकनीक भूमि प्रयोग मानचित्र तैयार करने में काफी सहायक तो सिद्ध हुई लेकिन भूमि प्रयोग की सभी किस्मों के विषय में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सकी। विशेषकर निर्मित क्षेत्र और खाली जमीन, व मझौले किस्म की हरियाली से मुक्त जमीन के प्रयोगों के बीच भेद कर पाने में काफी कठिनाई पेश आयी। इसके लिये भूमि प्रयोग को मौके पर जाकर देखना और जमीनी स्तर पर पुष्टि करना जरूरी था। आर एस से भूमि प्रयोग परिवर्तन के बाहरी पहलुओं को समझने में भी काफी मदद मिली। शहरीकृत होते क्षत्रों के लिये आर एस व्याख्या और डाटा प्रोसैसिंग की क्षमता में परिष्कार की काफी संभावनायें हैं।

शहरीकरण को अकसर पर्यावरणीय विनाश के साथ सीधे-सीधे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस संदर्भ में पड़ताल के लिये हमने जो दौरे किये उनसे पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से, जमीन की भौतिक विशिष्टताओं (मसलन पेड़-पौधों और मिट्टी) का क्षरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जमीन के प्रयोग और उसके लाभान्वितों, दोनों में विविधता आ रही है। जमीन के लेन-देन की रफ्तार में तेजी आयी है और जमीन को किसी खास उपयोग के लिये ढालना आसान हो गया है। कई बार भूमि प्रयोग की किस्मों के बीच तनाव भी होता है मसलन कृषि भूमि पर, ईंट भट्ठों के फायदे के लिये मिट्टी की खुदाई करना। ये काम न केवल खुदाई वाली जमीन के लिये (तात्कालिक तौर पर) नुकसानदेह हैं बल्कि नजदीकी खेतों के लिये भी हानिकारक हैं (मसलन मिट्टी का बहना और सिंचाई व्यवस्था का टूट जाना आदि) लेकिन, इन गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव भी हैं (जैसे लवणीय मिट्टी का हट जाना और जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित प्लॉटों का थोड़ा नीचा हो जाना)।

'पात्र पक्ष' पर नजर डालने से, जमीन को प्रभावित व विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के भीतर की स्थिति का अंदाजा लगाने का अवसर मिलता है। जब शहरीकरण आगे बढ़ता है तो उनके बीच विविधता का दायरा और फैल जाता है। जमीन के मामले में (भूतपूर्व) भू-स्वामी किसानों की अभी भी काफी चलती है। विस्थापित परिवारों की एक बड़ी संख्या रहने के लिये छोटे-छोटे प्लॉट ले लेती है जो अकसर अवैध होते हैं। दूसरे निजी कर्त्ताधर्ताओं की जमात में प्रॉपर्टी डीलर, सट्टेबाज, डेवेलेपर, उद्योगपति व अन्य उद्यमी आते हैं। सरकार इस खेल में अपने तरीके से दखल बनाती है। औपचारिक भू अधिग्रहण (जमीन के अधिग्रहण और विकास) पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) का एकाधिकार है। मगर इसका यह मतलब भी नहीं है कि डी डी ए मनचाहे तरीके से योजनायें बनानें में सक्षम है। यह निकाय गुणवत्ता और मात्र दोनों के ही लिहाज से–जमीन और हाऊसिंग उपलब्ध कराने के अपने काम में काफी कमजोर है। सुविधाओं के इस अभाव को दूर करने के लिये अनौपचारिक या गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलते हैं। जमीन के अनधिकृत लेन देन और विकास में गांवों के मूल निवासी भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जमीन की कमी, ढांचागत सुविधाओं की पूर्ति में कठिनाईयां और कई पर्यावरणीय चिंतायें औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रें के बीच के टकरावों की ही देन हैं।

विकास के भूगोलशास्त्र से संबद्ध अनेक जानकार (विशेषकर वे, जो राजनैतिक पारिस्थितिकी की वकालत करते हैं) (छोटे) किसानों और दूसरे (गरीब) स्थानीय परिवारों के लिये अलाभकारी स्थिति पर काफी जोर देते हैं। लेकिन, शहरी सीमा क्षेत्र में रोज-ब-रोज के क्रियाकलापों में उत्पीड़न का कोई सवाल नहीं उठता। जमीन की कीमतें और भू अधिग्रहण दरें काफी ऊंची हैं, इससे लोगों को जमीन के विनिमय से मुनाफा होता है और ग्रामीण मेहनतकशों को शहरी गतिविधियों में ऊंची तनख्वाहों का तत्व संतोष देता रहता है। यहां सबसे कमजोर समूह विस्थापितों का है, जिनके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, वे मामूली पारिश्रमिक पर काम करते हैं और कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, उनके पास कोई राजनैतिक शक्ति भी नहीं है।

शहरीकरण के कारण पेशे और आमदनी के अवसरों की सामाजिक-आर्थिक संरचना बेहद तेजी से बदलती जा रही है। गांव के स्तर पर 'स्थान' और 'परिस्थिति' के भौगोलिक पहलुओं पर यह बदलाव बेहद साफ दिखायी देता है। स्थान का बदलाव भूमि प्रयोग बदलावों, स्थानीय (गैर कृषि) आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और नागरिक सुविधाओं के फैलाव के रूप में दिखायी देता है, जबकि परिस्थिति शहर तक बेहतर पहुंच के परिणामस्वरूप बदलती है जहां एक विशाल श्रम बाजार मौजूद है और लगातार फैलता जा रहा है।

भारतीय ग्रामीण समाज की परंपरागत संरचना के आधार पर तीन समूहों को साफ-साफ एक-दूसरे से अलग करके देखा जा सकता है: मूल वर्चस्वशाली जाति(यों) से संबद्ध परिवार (समूह 1), गांव के दूसरे मूल निवासी परिवार जो ज्यादातर निचली जातियों से हैं (समूह 2), और विस्थापित परिवार (समूह 3)। यदि आजीविका के विषय में बात की जाये तो, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में परिवार शहरी किस्म के रोजगारों का उपयोग करते हैं। शहरीकरण के साथ जुड़े दूसरे आय स्रोतों (जैसे, मकान व जमीनों को किराये पर देना, खुदरा, व्यापार वगैरह) से जीवन स्तर में सामान्य वृद्धि होती है। समूह 1 अभी भी कृषि कार्यों से जुड़ा है लेकिन साथ ही सरकारी रोजगारों (मसलन,

बस ड्राईवर से पुलिस अफ़सर तक) में भी जाता है। इसके अतिरिक्त जमीन की खरीद फ़रोख्त, मकानों के किराये और जमीन को पटटे पर देने जैसे कामों से भी सबसे ज्यादा मुनाफ़ा समूह 1 को ही होता है क्योंकि इस समूह के पास (अभी भी) सूचना और संपर्क के बेहतर साधन हैं और वास्तविक राजनीतिक शक्ति से लैस है। परिणामस्वरूप, औसत जीवन स्तर के मामले में समूह 1 सबसे आगे है।

समूह 2 परंपरागत जाति आधारित जजमानी व्यवस्था के मुताबिक, पुराने समय में, छोटे पैमाने की कारीगरी, खेत मजदूरी और अन्य शारीरिक श्रम कार्यों पर निर्भर रहता था। यह समूह लगभग पूरी तरह शहरी रोजगारों (इनमें से अनेक लोग मजदूर से लेकर प्रशासनिक ओहदों और सरकारी नौकरी में भी गये हैं) और स्थानीय सेवाओं पर केंद्रित है। उनके परंपरागत जाति आधारित पेशे या तो नष्ट हो चुके हैं या उनका संस्थाकरण अथवा व्यवसायीकरण हो चुका है। समूह 2 तेजी से फ़ैलते स्थानीय खुदरा (रिटेल) क्षेत्र और मरम्मत आदि की दुकानों में विशेष रूप से सक्रिय है। फ़लस्वरूप इस समूह का जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है हालांकि समूह 1 की तुलना में इसका जीवन स्तर बहुत ऊपर नहीं उठ पाया है और इसकी प्रमुख वजह यह है कि इस समूह में पहले से कोई भी अत्यंत संपन्न परिवार नहीं थे।

समूह 3 क्रमशः सबसे निचले श्रमिक वर्ग की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, विशेषकर कृषि और औद्योगिक श्रम के विषय में। इन विस्थापितों को सामान्यतः अत्यंत घृणास्पद जीवन स्तर से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद, शहरी सीमांत क्षेत्र में वे कुछ आय अर्जित कर लेते हैं जो वे अपने मूल निवास क्षेत्र में अर्जित नहीं कर सकते थे।

अध्ययन का अंतिम पहलू शहरीकृत होते गांवों के भीतर और इर्द-गिर्द बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में है। इसके लिये एक पूरी तरह शहरीकृत व औद्योगिकृत हो चुके गांव की केस स्टडी का सहारा लिया गया है। उत्तरी दिल्ली स्थित समयपुर नामक इस गांव की मूल आबादी के भीतर और इर्द-गिर्द फ़ैक्ट्रियों, झौपड़पट्टी और बेकार जमीनों का बोलबाला है। भीड़-भाड़, प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं पर बेतहाशा दबाव की मूल समस्यायें शहरीकरण के बदहवास और अनियोजित ढर्रे की देन हैं। जीवन और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव सिद्ध हो चुके हैं। इसकी पड़ताल करना आसान नहीं है क्योंकि पर्यावरणीय पहलू ऐसे अनेक पहलुओं में से एक है। यही नहीं, लोगों की राय को भी वस्तुगत तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसके बावजूद, यह निष्कर्ष बेहिचक दिया जा सकता है कि यहां फ़ैलने वाली अनेक बीमारियां निवासियों की उन पर्यावरणीय परिस्थितियों की देन है जिसमें वे रहते, काम करते और घूमते फ़िरते हैं। विशेष आंतरिक संक्रमण (टी बी सी और पेचिश वगैरह), श्वास रोग, त्वचा इन्फ़ैक्शन और मनोवैज्ञानिक विकार बेहद आम हैं। अवैध फ़ैक्ट्रियों में काम के खराब हालात के कारण जो अनगिनत दुर्घटनायें होती हैं वे सीधे-सीधे इस गांव में हुए औद्योगिकरण के तरीकों के साथ संबंधित हैं।

शहरी विकास का एक पहलू साफ़ तौर पर सकारात्मक है कि इससे गांवों में संपन्नता का स्तर बेहतर हुआ है जिसके चलते लोग अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं और साथ ही उन्हें बेहतर नागरिक सुविधायें मिली हैं। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फ़ायदा गांवों के पुराने परिवारों को होता है। यहां चिकित्सा सुविधायें (बेहतरीन अस्पतालों से लेकर नीम हकीमों तक) ठेठ गांवों के मुकाबले कई गुना बेहतर पहुंच में है। दूसरी तरफ़ इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि शहरीकरण से आवासीय और व्यावसायिक किस्म की भूमि प्रयोग पद्धतियों का एक अनपेक्षित घालमेल पैदा हो जाता है और जनसंख्या

दबाव बेतरह बढ़ जाता है। अवैध फैक्ट्रियों के आस-पास रहने वाले परिवार और उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले (विस्थापित) मजदूर सबसे ज्यादा कमजोर तबका है। सबसे विपन्न विस्थापितों के लिये दैनिक भरण पोषण का सवाल पर्यावरणीय चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़ा है, और यदि वे अपने मूल निवास क्षेत्र में ही रहते तो निस्संदेह इससे भी खस्ता हालत में होते। बहरहाल, यदि नियोजन और भूमि प्रयोग संबंधी कानून शहरीकृत होते गांवों की खास स्थितियों के अनुरूप होते तो अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से बचा जा सकता था।

यह अपेक्षा स्वाभाविक ही है कि भविष्य में शहरी प्रभाव और भी विस्तार ग्रहण करेगा और कई नये गांव इसके दायरे में आ जायेंगे। इसके बाद भी, शहरी जमीन की भारी मांग और सरकारी विभागों के दोषपूर्ण संचालन के चलते आवासीय सुविधाओं की भयानक कमी बनी रहेगी। कमी को पाटने के लिये अनौपचारिक क्षेत्र एक अहम भूमिका निभा सकता है। अंततः ऐसा कहा जा सकता है कि गांव वालों को स्वतःस्फूर्त शहरी विस्तार से फायदे की संभावना रहती है, जिसके चलते शहरीकरण के जरिये उनकी आर्थिक और पेशागत स्थिति सुधारेगी।

Samenvatting

Ongeregelde urbanisatie aan Delhi's stadsrand,
veranderende patronen van grondgebruik en bestaanswijze

Het centrale onderzoeksthema van dit proefschrift betreft de gevolgen van urbanisatie op het ruraal-urbane randgebied van Delhi. Deze gevolgen omvatten vier delen: het grondgebruik, de 'actoren' met een rol in het grondgebruik en de lokale economie, de (veranderende) situatie van werk en inkomen onder de dorpsbevolking, en de kwaliteit van de leefomgeving.

De metropool Delhi telt ruim 13 miljoen inwoners en breidt snel uit onder invloed van een sterke bevolkingsaanwas (meer dan de helft door migratie), door expanderende economische bedrijvigheid en door incorporatie van dorpen in de stad. Dit laatste geschiedt in een tempo van een tiental dorpen per decennium. De dorpen die nog in het ruraal-urbane overgangsgebied liggen laten ook een sterke transformatie zien. Veranderingen in de lokale economische omgeving ('site') en de bereikbaarheid ('situation') hebben sterke gevolgen voor de beroepsoriëntatie van de bevolking in de vorm van forenseren en de ontwikkeling van lokale niet-agrarische activiteiten. Door bestudering van de secundaire data ontstaat weliswaar een beeld, maar we weten nog niet voldoende verbanden en details over het urbanisatieproces in de dorpen.

Voor het empirische deel van het onderzoek is gebruikgemaakt van diverse methoden. Huishoudenquêtes alsmede gerichte diepte-interviews waren het belangrijkste instrument voor het analyseren van de veranderende bestaanswijze. Voor het in kaart brengen van het landgebruik werden satellietbeelden gebruikt, en voor beleidsaspecten werden er kranten en andere media op nageslagen.

De invloed van de fysieke incorporatie van de dorpen in de stad op de leefomgeving wordt geïllustreerd met behulp van een casestudy, om zo ook het voorland van de nu nog relatief landelijke stadsranddorpen te verkennen.

De enorme dynamiek van het grondgebruik is een kenmerkend aspect van ruraal-urbane randgebieden van snelgroeiende steden zoals Delhi. Grondbestemmingen veranderen van agrarische naar urbane functies, grondprijzen stijgen snel, en veelvuldige transacties hebben tot gevolg dat ook de eigendomstructuur verandert. De volgende relevante klassen van grondgebruik domineren in het onderzoeksgebied, en illustreren de overgang van ruraal naar urbaan in de tijd en in de ruimte:

1. akkerbouw (afnemend onder invloed van urbanisatie)
2. tuinbouw en bloemen (licht toenemend door impuls van de stedelijke markt)
3. bos, communaal land en plantages (afnemend door bevolkingsdruk)
4. ongebruikt (in totaal stabiel, maar ruimtelijk veel verschuivend in de transitie naar een ander gebruik of voor speculatieve doeleinden)
5. steenfabrieken en ermee gelieerde afgravingen (nu weer afnemend door verschuiving naar verder weg gelegen platteland)

6. (luxe) buitenhuizen (toenemend)
7. infrastructuur (toenemend)
8. bebouwd (sterk toenemend, vooral illegale wijken, industrie en opslagplaatsen, maar ook geplande bebouwing).

Remote sensing (RS) in de vorm van satellietbeeldinterpretatie bleek nuttig, maar de RS analyse kon niet ieder type grondgebruik naar tevredenheid onderscheiden. Desondanks konden in combinatie met visuele interpretatie bruikbare kaarten worden gemaakt van het studiegebied. Bovendien verschafte RS inzicht in de fysieke kenmerken van elk type landgebruik. Er zit nog veel potentie in de verfijning van toepassing van RS in stedelijke randgebieden.

Urbanisatie wordt vaak in verband gebracht met milieudegradatie. Maar vanuit een sociaal-economisch perspectief is de eventuele aantasting van de fysieke eigenschappen van het land (bijvoorbeeld bodem en vegetatie) vaak niet relevant. Het gebruikersnut wordt steeds diverser, er wordt druk gehandeld en de grond is relatief makkelijk klaar te maken voor elk willekeurig gebruik. Soms zijn er spanningen tussen soorten grondgebruik, zoals het afgraven van landbouwgrond voor zand en klei, die niet alleen (tijdelijk) nadelig zijn voor de grond in kwestie maar ook voor aanliggende percelen landbouwgrond (bijvoorbeeld door erosie en verstoring van het irrigatiesysteem). Deze complexe relatie voorziet echter ook in positieve effecten (b.v. het afsteken van licht saline bodems en moeilijk te irrigeren hoger gelegen landbouwgrond).

De actorbenadering biedt inzicht in de betrokken personen, groepen en instituties die invloed en belangen hebben in grond. Naarmate de urbanisatie voortschrijdt neemt het aantal en de diversiteit van belanghebbenden toe. Bepaalde groepen binnen de lokale bevolking, vooral (voormalige) landbezittende boeren, blijven invloedrijk. Grote aantallen arme migrantenhuishoudens vinden op illegale manier een stukje land om te wonen. Andere belangrijke private actoren zijn grondmakelaars, speculanten, ontwikkelaars en industriëlen. De overheid mengt zich in het ‘spel’ in vele gedaanten. Eén van de belangrijkste instanties, de Delhi Development Authority (DDA), heeft een monopolie op de officiële stadsuitbreiding (onteigening en ontwikkeling van grond). Dit betekent niet dat de DDA de ruimte ongestoord kan plannen. De DDA schiet duidelijk tekort in zijn taak van de grond- en huizenbouwvoorziening. De informele sector springt in dit gat en bouwt op grote schaal illegale nederzettingen waarin ook de voorheen rurale dorpelingen vaak een belangrijke rol spelen. De schaarste aan grond, de moeilijkheden met de aanleg van infrastructuur en de milieuproblemen zijn terug te voeren op conflicten tussen de formele en informele actoren.

Veel bronnen uit de ontwikkelingsgeografie (vooral uit de hoek van de *political ecology*) benadrukken de ongunstige positie van (kleine) boeren en (armere) lokale huishoudens. In de dagelijkse praktijk van het stedelijk randgebied is echter meestal geen sprake van slachtoffering. De prijzen van de grond en de tarieven van onteigening zijn vrij hoog, de bevolking houdt een behoorlijke vinger in de pap, en participeert sterk in economisch aantrekkelijke stedelijke activiteiten. De zwakste groep zijn de migranten die geen erfrechten hebben in de dorpen, zeer laagbetaalde arbeid verrichten, en een speelbal vormen van autoriteiten en politici.

De sociaal-economische situatie van de dorpelingen verandert sterk onder invloed van urbanisatie. Op dorpsniveau is urbanisatie merkbaar in de geografische aspecten van ‘site’ en ‘situation’. De *site* verandert in de vorm van landgebruikveranderingen, meer

lokale bedrijvigheid en uitbreiding van het voorzieningenniveau, en de *situation* verandert als gevolg van betere verbindingen met de stad waar de (arbeid)markten zich sterk ontwikkelen.
Onder de dorpsbevolking is bij voorbaat een driedeling te onderscheiden op basis van de sociaal-economische uitgangspositie van huishoudens: de oorspronkelijke dominante (landbezittende) huishoudens (Groep I), de overige autochtone huishoudens die meestal bij lagere kasten behoren (Groep II) en de migrantenhuishoudens (Groep III). Aangaande de sociaal-economische bestaanswijze van de bevolking kan worden geconcludeerd dat verreweg de meeste huishoudens reeds gebruik (kunnen) maken van stedelijke werkgelegenheid. Ook inkomsten die nauw samenhangen met urbanisatie (verhuur van huizen en grond, (detail)handel, etc.) zorgen voor een algemene stijging van het welvaartspeil. Groep I houdt nog het sterkste vast aan agrarische inkomsten, maar integreert ook in grote getale in de stedelijke arbeidsmarkt, vooral in overheidsbanen (variërend van buschauffeur tot politieofficier). Groep I kan het meeste profijt trekken van landtransacties en verhuur van huizen en verpachten van land doordat de leden van deze groep (nog steeds) veel lokale macht en informatie bezitten. Groep I behoudt mede hierdoor duidelijk een voorsprong in gemiddelde levensstandaard. Groep II, oorspronkelijk afhankelijk van landarbeid en kleinschalige nijverheid in het kastengebonden Jajamani systeem, richt zich vrijwel geheel op stedelijke werkgelegenheid (ook veel in overheidsdienst, variërend van arbeider tot medewerker administratie), en lokale diensten en handel. De traditionele kaste-gebonden activiteiten worden losgelaten, geïnstitutionaliseerd of gecommercialiseerd. Vooral de groeiende kleine middenstand is in handen van Groep II. De gemiddelde levensstandaard stijgt, maar is duidelijk lager dan die van Groep I. Groep III neemt langzamerhand de positie van laagste arbeidersklasse over. Deze migranten hebben meestal te kampen met een abominabele levensstandaard. Echter, men vindt in de stedelijke randzone een bestaansmogelijkheid die er in hun gebied van herkomst niet is.
Het laatste aspect gaat over de veranderende leefomgeving in en rond de urbaniserende dorpen. Hiervoor wordt een casestudy gebruikt van een reeds volledig geürbaniseerd en verregaand geïndustrialiseerd dorp, waar het oorspronkelijke dorp verweven is met fabriekjes, sloppenwijken en verwaarloosd lager gelegen land. Uit de chaotische urbanisatie resulteert congestie, vervuiling en druk op de voorzieningen. Deze hebben sterk negatieve gevolgen voor de leefomstandigheden en de gezondheid van de bevolking. Dit is een lastig te onderzoeken onderwerp omdat omgevingsfactoren erg moeilijk zijn te relateren met gezondheid, en bij navraag de perceptie vaak afwijkt van de werkelijke situatie. Desondanks kan worden geconcludeerd dat de slechte leefomgeving vooral infectieziekten (bijvoorbeeld veel TBC), respiratoire aandoeningen, huidaandoeningen en psychische klachten (mede) veroorzaakt. De vele ongelukken in de fabrieken door de slechte werkomstandigheden zijn natuurlijk direct terug te voeren op het soort industrialisatie dat zich in dit dorp heeft voorgedaan.
Er is ook een positieve kant van stedelijke ontwikkeling in de vorm van de toegenomen welvaart die zorgt voor betere behuizing en een hoger voorzieningenniveau. Dit geldt voornamelijk voor de oorspronkelijke dorpsbewoners. Voorts dragen de alom aanwezige medische voorzieningen (variërend van kwakzalvers tot zeer capabele artsen) bij aan een betere toegang tot medische zorg, zeker in vergelijking met perifere plattelandsgebieden. Aan de negatieve kant leidt de ongeplande urbane uitbreiding tot vermenging van

residentieel, industrieel en commercieel landgebruik, en tot een enorme bevolkingsdichtheid. De huishoudens die zich nabij illegale industrie bevinden, en werkgelegenheid vinden in dezelfde industrie, vormen de meest kwetsbare groep (vrijwel uitsluitend migranten). Voor de migranten leggen milieuproblemen het af tegen de zorg om de broodwinning. Bovendien zijn de omstandigheden in de merendeels achtergebleven plattelandsgebieden waar men vandaan komt welbeschouwd nog ongunstiger. Niettemin zou een groot deel van de milieuproblemen te voorkomen zijn door middel van regels en planning die inspringt op het specifieke urbanisatieproces van stadsranddorpen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de stedelijke invloed zich over een steeds groter gebied gaat uitstrekken. Desondanks zal door de enorme vraag naar grond en het gebrekkig functioneren van overheidsinstanties het grote huizentekort blijven bestaan. De informele sector zal door middel van spontane stadsuitbreiding mee moeten helpen. Dit over het algemeen overigens niet tot verdriet van de lokale dorpelingen, die op deze manier veel vaker profiteren van baten die voortkomen uit urbane ontwikkeling.